ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

रविवारीय 01-07 सितंबर 2019, संस्करण-1, अंक -4 | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN 00962 | कुल पृष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

पेज: 4

झारखंड से होकर नहीं रूक रही गौतस्करी

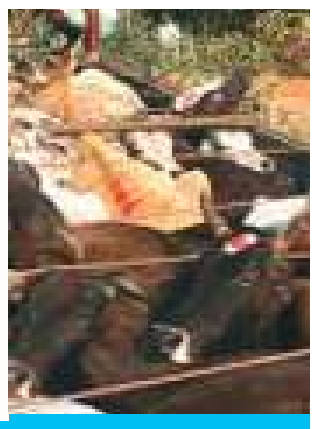

ग्रीन रिवोल्ट आप सभी पाठकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकानायें देता है।

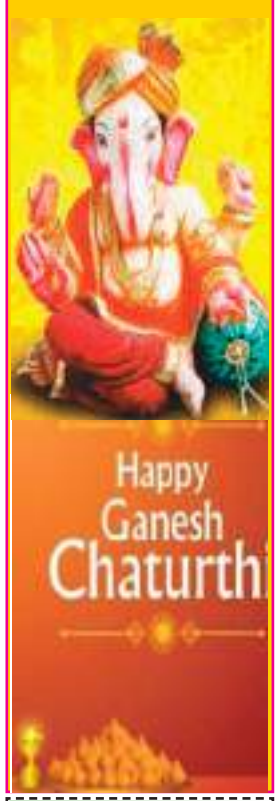

सूचना

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी, पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

क्या भयंकर लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा थी मूरी हिंडाल्को दुर्घटना?

रांची : अप्रैल 2019 में मूरी के हिंडाल्कों कारखाने में एक दुर्घटना हुयी थी जिसमें कारखाने की दीवार तोड़ कर लाल कीचड़ का सैलाब बह कर बाहर दूर दूर तक फैल गया था। ये वाकया कुछ ऐसा ही था जैसे बरसात में कोई पहाड़ टूट जाये और उसके अंदर से मलबा कीचड़ एकाएक बाढ की शक्ल में रिहायशी इलाके में आ जाये। इस दुर्घटना के बाद बहुत शोर गुल हुआ, सैकड़ो लोगों, मवेशियों के इसमें दबे होने की बात कही गयी, लेकिन इसे खुशक्स्मिती कहें या संयोग कि इस वाकये में किसी के जान जाने की सूचना बाद में भी नही आयी। सिर्फ कुछ वाहन और जेसीबी इसकी चपेट में थे।

जब ग्रीन रिवोल्ट ने इस मामले को करीब से देखा तो ये बात निकल कर सामने आयी कि इस मामले में लापरवाही बरती गयी थी। जो तथ्य हमें प्राप्त हुये उसके अनुसार देखें तो सिर्फ हिंडाल्को ही नही राज्य के बहुत सारे कारखानों में सुरक्षा के इंतजाम सही नहीं हैं और समय समय पर उपकरणों से लेकर निर्माण तक की जांच के नाम पर खानापुर्ति होती है।

हिंडाल्कों फैक्ट्री में बॉक्साइट के मलबे को डंप कर रखा जाता है। इसी मलबे का लाल कीचड़ डंपिंग यार्ड के बाउंड्री को तोड़ते हुये आधे किलो मीटर तक बाहर फैलता चला गया था। यह मलबा रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया था और इसकी चपेट मेंआने से 10 एकड़ खेत भी बर्बाद हुये थे। सवाल है कि, जिस कंपनी भारत इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्सन ने इस

चीफ कारखाना नीरीक्षक पर चहेती कंपनियों से ही ऑडिट करवाने का दबाव देने का आरोप जेनरल इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग आर्गेनाइजेसन के एस के चतुर्वेदी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि मूरी हादसे में मुख्य कारखाना नीरीक्षक के चहेते सुभाष कुमार की कंपनी भारत इंस्ट्रियल कंस्ट्रक्सन को ही ऑडिट का काम दिया गया था।

हादसे से पहले प्रत्येक उपकरणों से लेकर सिविल स्ट्रक्चर की जांच की और सब कुछ सही होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया उसने क्या जांचा? ऑडिट करने वाली कंपनियों को एक साल का लायसेंस मिलता है जिसमें वो कारखानों में सुरक्षा के उपायों से लेकर कर्मचारियों की सुरक्षा, महिला कर्मियों की सुरक्षा के इंतजाम तक की जांच करते हैं। सिविल स्ट्रक्चर की जांच हर तीन साल पर की जानी होती है, वहीं उपकरणों की जांच को स्टेबिलिटी टेस्ट कहते हैं जो प्रतिवर्ष की जानी होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक निर्णय दिया है कि किसी भी खतरनाक कारखाने में प्रति 200 कर्मचारियों पर एक सुरक्षा अधिकारी को रखना अनिवार्य है वहीं कम खतरनाक कारखानों में प्रति 500 कर्मचारियों पर एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है। जाहिर इतने सारे नियमों कानूनों का पालन संजीदगी ने कारखानों में नहीं होता है इसी कारण से हादसे भी होते हैं, जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं।

ऑडिट कंपनी या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती

इस हादसे के बाद उच्च स्तरीय कमिटी बनी थी जिसमें मामला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेवारी का बनता है। क्योंकि कीचड़ को फैक्ट्री एरिया से बाहर सड़क की दूसरी ओर डंप किया गया था। फैक्ट्री से बाहर के किसी भी मामले में हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती।

अरूण कुमार मिश्र

चीफ कारखाना नीरीक्षक

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय चना समूह के वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन

चना फसल की खेती में झारखण्ड का बेहतरीन प्रदर्शन : कुलपति डॉ. आरएस कुरील

देश अब दलहन के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ रहा है कुलपति :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में देश के दलहन विशेषज्ञों की 24वीं राष्ट्रीय समुह की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची एवं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान,कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), नई दिल्ली के सौजन्य से पूरे देश के 24 राज्यों के 28 कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत अखिल भारतीय समन्वित चना अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) से जुड़े वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

मौके पर कुलपति डॉ कुरील ने कहा कि विगत तीन वर्षो में देश ने दलहन उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की है। वर्ष 2016-17 में देश में दलहन का उत्पादन 18 मिलियन टन था केंद्र के सहयोग आईसीएआर द्वारा वर्ष 2017-18 में दलहन हब कार्यक्रम चलाये जाने से देश में 22 मिलियन टन दलहन का उत्पादन हुआ। जो वर्ष 2018-19 में 25 मिलियन टन तक पहुँच गया। देश में दलहनी फसलों के उत्पादन में चना फसल का करीब 40 प्रतिशत योगदान है। देश में धान की परती पड़ी भूमि में चना की खेती का रकबा बढ़ाने की काफी संभावनायें है।

राज्य में चना की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

कुलपति ने बताया कि देश में पिछले 12 वर्षो में दलहन फसलों का रकबा एवं उत्पादन में दुगुनी बढ़ोतरी हुई है। दलहन के आयात में कमी आई है। देश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। देश को दलहन आयातक की जगह निर्यातक बनाने की आवश्यकता है। बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए कृषि वैज्ञानिकों को कम अवधि में तैयार होने वाली तथा अधिक उपज देने वाली फसल किस्मों के विकास करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में चना फसल के क्षेत्र में झारखण्ड का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। राज्य में करीब 18 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती की जाती है। इनमें करीब 14.6 लाख हेक्टेयर धान की परती पड़ी भूमि में चना तथा राई-सरसों की खेती को बढावा दिये जाने की जरूरत है तथा कम अवधि व उच्च उपजशील प्रभेद के विकास पर प्राथमिकता देने की जरूरत है। इससे झारखण्ड के किसानों की आय दुगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा।

मौके पर कुलपति ने दलहन शोध में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय दलहन सोसाइटी की ओर से कुलपति डॉ कुरील ने इक्रीसेट के निदेशक डॉ राजीव कुमार वासनी को फेलो साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा। एआईसीआरपी का वार्षिक प्रतिवेदन (2018-19),परियोजना समन्वयक प्रतिवेदन (2018-19) तथा झारखण्ड में चना की वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा उन्नत खेती नामक पुस्तक का विमोचन किया. इस वर्ष रिटायर हो रहे चना समूह के तीन वैज्ञानिक डॉ बीके झांगवाल, डॉ एलबी माशे और डॉ डीएम महालिंगा को कुलपति ने सम्मानित किया। बैठक में वार्षिक रपट प्रस्तुत करते हुए आईपीआरआई के परियोजना समन्वयक डॉ जीपी दीक्षित ने बताया कि वर्ष 1993 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), नई दिल्ली के सौजन्य से भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, शेष पेज 3 पर...

प्रतिकूल परिस्थितियों में भी झारखंड में वनों का हुआ विस्तार

झारखंड जैसे राज्य में जहां खनिजों की प्रचुरता है और जहां तहां खदान हैं, उद्योगों की संख्या ज्यादा है, वहां वनों के क्षरण की ज्यादा संभावना होती है। आज हर जगह से वनों के नष्ट होने और वन क्षेत्रों के सिकुड़ने की खबरें ज्यादा आती हैं ऐसे में अगर झारखंड में वन क्षेत्र में वृद्धी हुई है, तो इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखनी चाहिये।

रांची : भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा सैटेलाइट इमेज के आधार पर निर्मित स्टेट आफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 तक झारखंड राज्य में वन क्षेत्रों में 373 वर्ग किमी की वृद्धी दर्ज की गयी है। इस प्रकार 2013 के मुकाबले 2017 में झारखंड के कूल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.47 प्रतिशत वन क्षेत्र बढा। 2017 के उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वन एवं वृक्षावरण बढ़ कर राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.21 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार राष्ट्रीय वन नीति 1988 में निर्धारित लक्ष्य को झारखंड राज्य ने पहली बार पूरा कर लिया।

वन विभाग के अनुसार हाल के कुछ सालों में उसने एक प्लान बना कर वनों के विस्तार के लिये ठोस काम करने शुरू किये तब जाकर एक अच्छी तस्वीर उभरी है। वन विभाग ने कई ऐसे कार्यक्रम चलाये हैं जिनसे राज्य में वनों के विस्तार में मदद मिली है।

वनों का प्राकृतिक पुनर्जनन : एक कार्यक्रम है। 36310 हेक्टेयर (जो कूल वनभूमि का डेढ प्रतिशत है) जिसमें वन संवर्द्धन , जल सह भू संरक्षण बांस बखार के सफाई कार्य वृहत पैमाने पर पिछले साल से प्रारंभ की गयी है। इस योजना में वहां के प्राकृतिक पौधों को ही फिर से उगाने की कोशिश की जाती है। ताकी स्थानीय प्रजाति के वृक्षों की ही तादाद बढ़े। इससे अधिक बायोमास वन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है।

मुख्यमंत्री जन-वन योजना : यह योजना 2016 से चल रही है। इस योजना में छह लाख से ज्यादा पौधे राज्य भर में लगाये गये हैं। पौधा रोपण में 75 प्रतिशत लागत का लाभुक को ही डीबीटी भुगतान कर दिया जाता है।

नदियों का पुनर्जनन : वर्ष 2018-19 में 409 किमी नदी तट पर 16 लाख पौधा रोपण किया गया।

वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना: वर्ष 2018 में 206 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जहां वृक्षारोपण किये गये।

सालों से लंबित मामलों को निबटाया गया: वन विभाग में कई ऐसे काम 30 सालों से लटके हुये थे जो आवश्यक थे। हाल के कुछ वर्षों में वन विभाग ने इस शिथिलता की स्थिति से खुद को उबार कर तेजी से कई मामले निबटाये। जैसे 2017 में वनरक्षियों की नियुक्ति की गयी, वन क्षेत्र के पदाधिकारी पद की नियमावली का सुत्रण किया गया। वर्षों से लंबित एसीपी और एमएमसीपी मामलों में से अधिकांश का निवारण कर दिया गया। लंबति प्रोन्नतियों के मामले को भी निबटाया गया। संविदा पर बहुत सारी नियुक्तियां की गयी। प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।

अगर सुक्ष्मता से अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि वन विभाग ने कई मोर्चों पर काफी परिश्रम किया है और परिणाम वन क्षेत्र के विस्तार के रूप में दिखा है। झारखंड सरकार और वन विभाग के लिये हाल ही में एक अच्छी खबर ये भी आयी है कि कैंपा फंड के माध्यम से राज्य को 4158 करोड़ रूपये की राशि मिली है। केंद्र में अर्से से पड़े इस राशि को राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। यह राशि राज्य में खनन और उद्योग धंधों के निर्माण के दरम्यान नष्ट हुये वन क्षेत्रों के मुआवजे के तौर पर दी जाती है। इनके सही इस्तेमाल से राज्य में वनों का और विस्तार संभव होगा।

हर आँगन, एक वृक्षारोपण

एक मुहिम स्वच्छता अभियान के तहत

''हर आँगन, एक वृक्षारोपण"गर्मी सबको लगती है पर पेड़ कोई लगना नहीं चहता है ।फलों का मजा सब लेना चाहते है पर पर कोई पेड़ लगना नहीं चहता है। छाया भी सभी को चाहिये पर पेड़ लगने का सोचना भी नहीं है ।शहरों में बढ़ते हुए प्रदूषणों को और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को देखते हुए "महर्षि सेवा संस्थान" और "मनोहर लाल स्मृति" सयुक्त तत्वाधान एक मुहिम चला रहा है, जिसमे हमरी संकल्प है की ''हर आँगन,एक वृक्षरोपण ''मैं मोदी जी के स्वच्छता अभियान से बहुत प्रेरित हूँ ।दरअसल शहरों को प्रदूषित कौन करता है ? यही पर रहने वाले लोग पर सफाई या प्रदूषण कम करने के लिये हम केवल सरकर को जिम्मेदार मानते हैं जबकी प्रदूषण हम करते है । जब प्रदूषण हम करते है तो सफाई करने और प्रदूषणों को रोकने का कुछ फर्ज हमारा भी बनता है । इसलिये हमारी तरफ से आप सभी को उपहार के रूप में 1 से 5 पौधा अपने घर मे लगने के लिए (जो भी आप लेना चाहो) देना चाहूँगा। स्कूल,कॉलेज या अन्य जगह के लिये 100 पौधे भी दिये जायेंगे।

यदि आप मुझसे वादा करे की आप उस पौधा को अपने घर के आँगन एवं संस्थान मे लगायेंगे और उस पौधे की देखभाल करेंगे। इसके लिए आप हमें 7004115578 राजीव जी और 8271201223 सुनिल जी को फोन करके पौधे ले सकते हैं ।ऐसा करने से शहर में हजारों वृक्षारोपण होगा जिससे वृक्षों द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। शहर की सुंदरता भी बढेगी।

विनती

महर्षि सेवा संस्थान और

मनोहर लाल समृति

लोकगायकों एवं युवा पत्रकारों को किया सम्मानित

रांची : प्रेस क्लब रांची ने 27 अगस्त को लोकगायिका चंदन तिवारी , मधुश्री, पत्रकार आनंद दत्ता एवं कार्निलियुस मिंज को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ रमेश पांडेय, रांची सांसद संजय सेठ, खेल एवं कला संस्कृति एवं युवा कार्य मंत्री अमर कुमार बाउरी थे। इस अवसर पर रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह, सचिव शंभू नाथ चौधरी सहित राजधानी के , जाने माने पत्रकार, कलाकार उपस्थित रहे। पत्रकार आनंद दत्ता को मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के दरम्यान सराहनीय काम करने के लिये सम्मानित किया गया। वहीं संघर्षशील पत्रकार कार्निलियुस मिंज को अब तक के पत्रकारिता में उनके योगदान के लिये सम्मानित किया गया। लोकगायकी और झूमर जैसी विधा को जीवित करने के लिये दोनों गायिकाओं को सम्मानित किया गया।

केंद्र से कंपेन्सेटरी एफोरस्टेसन फंड के 4158 करोड़ रूपये झारखंड को मिले यह राशि वन संवर्द्धन में खर्च होगी

कैंपा फंड मिलने पर मुख्यमंत्री ने आभार जताया

रांची :कैम्पा फंड (कंपेन्सेटरी एफोरस्टेसन फंड) पिछले 10-15 वषों से केंद्र के पास जमा थी, जिसका 90 प्रतिशत राज्य सरकारों को दे दिया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कैंपा फंड से झारखंड को 4158 करोड़ रूपये की राशि मिलने पर प्रधानमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि के मिलने से झारखंड में वन लगाने के काम में और तेजी आयेगी।

कैंपा फंड पाये राज्यों की सूची एवं राशि

1	Odisha	[illegible]
2	Chhattisgarh	[illegible]
3	Madhya Pradesh	[illegible]
4	Jharkhand	[illegible]
5	Maharashtra	[illegible]
6	Telangana	[illegible]
7	Uttarakhand	[illegible]
8	Uttar Pradesh	[illegible]
9	Rajasthan	[illegible]
10	Andhra Pradesh	[illegible]
11	Himachal Pradesh	[illegible]
12	Arunachal Pradesh	[illegible]
13	Gujarat	[illegible]
14	Karnataka	[illegible]
15	Haryana	[illegible]
16	Punjab	[illegible]
17	Assam	[illegible]
18	Bihar	[illegible]
19	Sikkim	[illegible]
20	Manipur	[illegible]
21	Goa	[illegible]
22	West Bengal	[illegible]
23	Mizoram	[illegible]
24	Tripura	[illegible]
25	Meghalaya	[illegible]
26	Tamil Nadu	[illegible]
27	Kerala	[illegible]
	Total	[illegible]

क्या होता है कैंपा फंड?

यह फंड उन कंपनियो द्वारा केंद्र में जमा किया जाता है जिन्होंने राज्य की वन भूमि का उपयोग उद्योग लगाने या खनन एवं कंस्ट्रक्सन कार्य के लिये किया है। इससे जो वन क्षति हुयी, उसके भरपाई, संरक्षण, संवर्द्धन एवं पर्यावरणीय संतुलन के लिये इसका उपयोग किया जायेगा। राशि के उपयोग के लिये राज्य प्राधिकरण कार्यकारी समिति कैंपा, स्कीम बना कर अनुमोदन के लिये मुख्य सचिव के अध्यक्षता में राज्य प्राधिकरण संचालन समिति को भेजेगी। समिति स्कीम को अनुमोदित कर भारत सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजेगी। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होते ही राशि का उपयोग होने लगेगा।

संजय श्रीवास्तव

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैंपा)

सीएमपीडीआई में मना स्वच्छता पखवाड़ा

रांची :स्वच्छता अभियान के तहत बिरसा उच्च विद्यालय कांके रोड में छात्र छात्राओं ने दौड़ में हिस्सा लिया। हाथों में स्वच्छता का संदेश वाला बैनर लिये छात्रों के दौड़ का समापन सीएमपीडीआई परिसर में हुआ। वहां स्वर्णरेखा हॉल में आशु प्रतियोगिता भी हुई। महाप्रबंधक एचआरडी बसु और आलोक कुमार ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता का महत्व बताया।

बालाजी डेंटल केयर

समस्त दंत रोगों की चिकित्सा उपलब्ध।

Address: Shiv Bhawan, Laah Kothi, Ratu Road, Ranchi-5

Ph. 9006833759

ऊजाड़ होते हाइवे

किसी भी राज्य की पहचान उसकी सड़कें होती हैं। खराब सड़कें विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं। दशकों तक बिहार झारखंड जैसे राज्य अच्छी सड़कों से महरूम रहे। इन राज्यों का सड़कों को लेकर उपहास उड़ाया जाता था और यहां की खराब सड़कें राष्ट्रीय बहस का विषय थे। कभी लालू यादव ने बिहार की सड़कों को लेकर एक चर्चित नायिका के सौंदर्य तक से तुलना कर डाली थी। झारखंड में तो एक सड़क और उसके निर्माण का मुद्दा इतना तूल पकड़ा था कि सरकारें तक गिर बन गयीं। रांची टाटा मार्ग को ही हम देखें तो राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क अपनी लेट लतीफी के कारण चर्चा में रहा है। कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ा, तीखी टिप्पणी की गयी। सड़क अभी तक नहीं बनी है।

रांची से टाटा के बीच अंतहीन समय से सड़क निर्माण में हजारो पेड़ काटे डाले गये। सड़क का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसमें हजारों पेड़ों को काट कर उसकी कीमती लकड़ियों को गायब करने का घोटाला भी चर्चा में था। दुसरी ओर हमने पेड़ों को काटने के बजाय उनके शिफ्टिंग पर कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। कुछ मामलों में सिर्फ इसकी खानापूर्ति की गयी।

हालांकि हाल के कुछ वर्षों में झारखंड के कई जिलों के बीच सड़कों का चौड़ीकरण का काम चल रहा है और आगें काम पूरा होते ही यातायात में सुगमता भी दिखेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने पिछले कार्यकाल में कई बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। लेकिन इन सबकी एक बहुत बड़ी कीमत राज्य को चुकाना पड़ा है। कई हाइवे अब उजाड़ हो गये हैं। सड़क चौड़ीकरण में उन पुराने घने छायेदार वृक्षों को काट दिया गया जो कभी उन सड़कों की पहचान हुआ करते थे। कई लोगों का कहना है कि इन सड़कों से अब यात्रा करते समय बहुत मायूसी होती है। पहले किनारों के पेड़ों की छांव में वो कुछ पल सुकून के लिये रूकते भी थे। अब सब वीरान हो गया है।

विकास के लिये अच्छी सड़कों का होना जरूरी है और चौड़ी सड़कों के निर्माण में वृक्षों की कटाई भी होगी । ऐसा नियम है कि निर्माण या खनन के दरम्यान जितने वृक्ष काटे जाते हैं, उससे ज्यादा वृक्षारोपण करना होता है। लेकिन प्रायः इसमें ईमानदारी नहीं होती। और अगर रांची टाटा रोड निर्माण में हजारो पेड़ काटे गये तो पेड़ उसी इलाके में लगें तभी इसका लाभ होगा। अन्यथा एक क्षेत्र बिल्कुल उजाड़ होता चला जायेगा और दूसरे में हरियाली होगी। जंगलो का यह असमान वितरण होगा। इसके अलावा ईमानदारी से यह जांच कौन करेगा कि जितने पेड़ काटे गये उसकी भरपाई सही सही हुई या नही?कई हाइवे निर्माण में ऐसा भी हुआ है कि, सड़कों के चौड़ीकरण में यह गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गयी कि, वहां वृक्ष लगा कर कुछ सालों बाद उसे फिर से हरा भरा सुकूनदेह बनाया सके।

जलवायु परिवर्तन पर कदम और उनकी भू-राजनीति

जलवायु के अनुकूल तकनीक पर नियंत्रण ही भविष्य में भू-राजनैतिक शक्ति का माध्यम बनेगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं *नितिन देसाई।*

जून और जुलाई 2019 दर्ज इतिहास के सबसे गर्म महीनों में शामिल रहे हैं और 2015 से 2019 तक का समय सबसे गर्म पांच वर्ष का समय रहा है। भारत में दिल्ली के पालम में 10 जून, 2019 को 48 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान में तापमान बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर गया। यूरोप और अमेरिका में भी अप्रत्याशित गर्मी देखने को मिली। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान के महासचिव पेटेरी टालास के मुताबिक अत्यधिक गर्मी के साथ-साथ ग्रीनलैंड, आर्कटिक और यूरोपीय ग्लेशियरों में जमकर बर्फ पिघली। आर्कटिक में लगातार दूसरे महीने जंगलों में आग लगी और वे घने जंगल नष्ट हो गए जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते थे और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करते थे। यह कोई विज्ञान गल्प नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की हकीकत है। अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में हालात और खराब होंगे।

ये गर्म हवाएं केवल नमूना भर हैं। यदि हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो हालात और खराब होंगे। बाढ़, सूखा, बारिश में कमी, तूफानों का आना, तटीय इलाकों के मीठे पानी में खारापन, कृषि एवं जैव उत्पादकता पर असर बढ़ेगा। कुलमिलाकर जलवायु से जुड़ी आपदाएं बढ़ेंगी और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। दुनिया का कोई देश अपने दम पर इससे निपट नहीं सकता क्योंकि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन समूची पृथ्वी पर असर डालने वाला है। यही कारण है कौन क्या करता है और किसे क्या करने को मजबूर किया जाता है, इसकी भू-राजनीति अब जलवायु कूटनीति की चिंता के मूल में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर 2019 में जलवायु परिवर्तन पर बहस होने वाली है, उससे कुछ संकेत निकल सकते हैं।

नेचर पत्रिका के एक हालिया आलेख में जलवायु परिवर्तन की भू-राजनीति के चार संभावित परिदृश्यों पर चर्चा की गई है। पहला परिदृश्य काफी हद तक अकल्पनीय है। इसमें विभिन्न देशों के बीच बोझ की साझेदारी के मामले में गहन सहयोग की बात की गई है। जीवाश्म ईंधन कंपनियों को वित्तीय बाजार के माध्यम से हाशिये पर करने, हरित तकनीक वाली कंपनियों के उभार और सभी देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही गई है। दूसरा परिदृश्य एक तकनीकी बदलाव की परिकल्पना करता है, जहां स्वच्छ ऊर्जा की आर्थिकी में नाटकीय बदलाव की बात कही गई है। इसका एक समतुल्य उदाहरण मोबाइल फोन तकनीक से लिया जा सकता है जिसने दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति ला दी। परंतु यह परिदृश्य कुछ देशों के बीच तकनीकी दबदबे और प्रतिद्वंद्विता की तस्वीर भी पेश करता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन आज ऐसे किसी कदम के बारे में पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

तीसरा परिदृश्य बढ़ते लोकलुभावन राष्ट्रवाद का एक जोखिम भरा चित्र

प्रस्तुत करता है जहां उत्सर्जन में कमी के तमाम प्रयास ठप होने की बात है। चौथा परिदृश्य वह है जो हम अभी कर रहे हैं। यानी पेरिस जैसे कमजोर समझौते। इससे कुछ सहायता मिलेगी लेकिन हम ताप वृद्घि के तय लक्ष्यों से पीछे रह जाएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि लोकलुभावन राष्ट्रवाद के परिदृश्य से गुजर रहे है। ट्रंप प्रशासन पेरिस समझौते की आलोचना कर चुका है, यूरोप में क्षेत्रवाद बढ़ रहा है और वहां प्रवासियों को लेकर चिंता बढ़ रही है।

लैटिन अमेरिका और यूरोप के कई देश वैश्वीकरण को नकार चुके हैं। इनमें से कई देशों में दक्षिणपंथी सरकारें हैं जो मानवजनित जलवायु परिवर्तन तक को स्वीकार नहीं करतीं। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन पर कदम उठाने को लेकर आम जन का प्रतिरोध बढ़ेगा क्योंकि ऐसी घटनाएं भी बढ़ेंगी। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 5 फीसदी जबकि चीन की 25 फीसदी है। हालांकि 2030 तक दोनों की हिस्सेदारी 20-30 फीसदी रहेगी और उन पर कदम उठाने का जबरदस्त दबाव होगा। बहुराष्ट्रवाद के क्षरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह व्यापार, तकनीक हस्तांतरण या वैश्विक पूंजी बाजार की मदद से एकतरफा दबाव में तब्दील हो जाएगा। भारत और चीन को प्रतिक्रिया देनी चाहिए और खुद को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदमों का अगुआ बनाना चाहिए।

कार्बन ऐक्शन ट्रैकर्स भारत की पेरिस प्रतिबद्घता को वैश्विक सहयोग की आवश्यकता के अनुरूप आंकता है। हालांकि वह चीन की प्रतिबद्घता को काफी कम मानता है। दोनों देश पेरिस प्रतिबद्घता की लीक पर हैं बल्कि वे वादे से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक हालिया अध्ययन यह भी बताता है कि चीन का उत्सर्जन पेरिस समझौते में किए उल्लेख से एक दशक पहले ही उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। जहां तक बात है जलवायु से जुड़ी भू-राजनीति की तो दोनों बड़े देशों में काफी कुछ एक समान है। दोनों का हित इसी में है कि अतीत के उत्सर्जन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में दोनों देश मिलकर काम करें तो भविष्य के विकास के लिए मौजूदा कार्बन स्पेस में उचित दखल कायम करें। दोनों देशों में तेल की कमी है और सौर तथा पवन ऊर्जा को वे केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी के विकल्प के अलावा ऊर्जा सुरक्षा के उपाय के रूप में भी देखते हैं। दोनों देश कोयले पर काफी हद तक निर्भर हैं और कोयले का इस्तेमाल कम करने तथा नई तकनीक विकसित करने तथा अपनाने में दोनों के हित जुड़े हैं।

तथ्य यह है कि घरेलू विकास के लिए हमें प्रभावी जलवायु कार्य योजना की आवश्यकता है। कोयले पर निर्भरता के अलावा दोनों देश जलवायु के अनुकूल वृद्घि के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में वास्तविक नेतृत्व तभी मिलेगा जब वे दूसरों से कुछ अलग कदम उठाएं। उन्हें जो गुंजाइश बनानी है या सार्वजनिक परिवहन, भवन डिजाइन, शहरी नियोजन, ऊर्जा किफायत वाले विनिर्माण आदि के क्षेत्र में जिस पैमाने पर जलवायु के अनुकूल तकनीक इस्तेमाल करनी है, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी। ये दोनों देश यह काम करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उनकी इमारतों, शहरी क्षेत्र, विनिर्माण क्षमता और बिजली संयंत्र आदि अभी बनने हैं। आवश्यकता केवल यह समझने की है कि जलवायु के अनुकूल तकनीक पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। जो देश ऐसा करने में कामयाब रहेगा वही भविष्य में भूराजनैतिक शक्ति का स्रोत बनेगा। चीन पहले ही इस राह पर बढ़ चुका है और भारत अगर जलवायु परिवर्तन की भूराजनीति में पिछड़ना नहीं चाहता तो उसे भी ऐसा करना होगा।

जनसंख्या पर ब्रेक लगे, तभी बचेगा पर्यावरण

अनिल पी जोशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए बढ़ती जनसंख्या पर ठीक ही चिंता व्यक्त की है। इस समस्या का हल किए बगैर हमारा जीवन सहज नहीं हो सकता। 2030 आते-आते भारत आबादी में चीन को पीछे छोड़ने वाला है। अर्थव्यवस्था के मामले में हो न हो लेकिन जनसंख्या में दुनिया में सबसे अग्रणी भारत ही होगा। इसका सीधा असर हमारे संसाधनों पर दिखेगा और सबसे पहला संकट पानी के अभाव के रूप में आएगा। जो दूसरे घटते प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे हवा, मिट्टी और जंगल, वे प्रत्यक्ष रूप में अपना प्रभाव तो नहीं दिखाते लेकिन पानी हमारी तमाम व्यवस्थाओं को चरमरा देगा। कहा जा रहा है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 अरब हो जाएगी। सोचा जा सकता है कि तब प्राकृतिक संसाधनों के लिए कितनी मारामारी मचेगी।

अराजकता की ओर

ऐसे में सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए कि हम किस तरह अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करें। 'हम दो हमारे दो' का नारा देश में बहुत फिट नहीं बैठा। अगर इसे लोगों ने गंभीरता से लिया होता तो हमारी जनसंख्या बढ़ती नहीं जाती। सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ हमारा जीवन बेहतर होता गया जिससे औसत आयु बढ़ी और जनसंख्या भी बढ़ती गई। अगर 2050 तक आने वाले संकट पर गंभीरता से नहीं सोचा गया तो क्या पानी और क्या पेट, दोनों बड़े संकट में चले जाएंगे। तमाम तरह की गोष्ठियों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को अन्य मुद्दों पर केंद्रित करने की बजाय जनसंख्या के मसले की ओर मोड़ें, तभी शायद हम इस पर नियंत्रण ला पाएंगे। भारतीय प्रशासन का रुख उदारवादी रहा है, लिहाजा जनसंख्या के मामले में लोगों को कई तरह की छूट दे दी गई है-कभी धर्म की आड़ में तो कभी अन्य कारणों से। जब तक हम इस मामले में एक समान नीति नहीं लाएंगे,

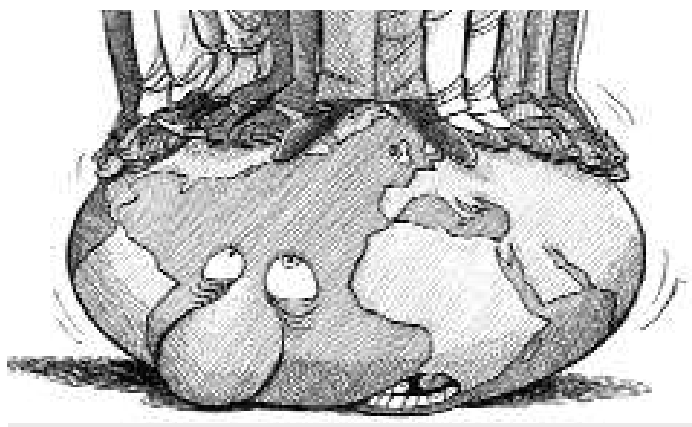

2030 तक भले हम अर्थव्यवस्था के मामले में फिसड्डी रहें, पर आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। वर्तमान में सरकारें जिस रफ्तार से लोगों की बूनियादी जरूरतों के इंतजाम के लिये प्रयासरत हैं वह आगे अपर्याप्त साबित होंगी। सरकारों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि, वो सब कुछ इंतजाम कर दे। बढती आबादी पर अंकुश की चेतना आम जनता में भी होनी चाहिये।

तब तक इसमें कोई अंतर नहीं आ आएगा। देश सबका है, सबको जिम्मेवारी लेनी होगी। सबको जनसंख्या संबंधी नियमों का पालन करना पड़ेगा चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो।

अगर आज ही बड़े निर्णय नहीं लिए गए तो बढ़ती जनसंख्या भारी अराजकता पैदा करेगी। सबके हिस्से में भरपेट भोजन ही नहीं होगा तो फिर हम किस मुंह से खुद को विकसित देश कह पाएंगे। एक नजर प्राकृतिक संसाधनों और उससे जुड़े उत्पादों पर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले समय में सबसे बड़ी मार इन पर ही पड़ने वाली है। अगर किसी तरह से हम खेती-बाड़ी को मैनेज भी कर लें तो भी उनसे जुड़े संसाधनों की उपलब्धता प्रकृति से ही संभव होगी। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि आज एक हेक्टेयर खेती 22 टन धान पैदा करती है और उससे 1000 लोगों का ही पेट भरेगा। पिछली सदी के विपरीत इस सदी में न जमीन बढ़ने वाली है, न ही उसकी उत्पादकता और यह मात्र मनुष्यों का ही नहीं, अन्य जीवों के पेट का भी सवाल है। वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार, अगर दुनिया की आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें डेढ़ गुनी बड़ी पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। बात भोजन की ही नहीं, पानी की भी है जो तीन दशक पहले लगभग 5000 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध था पर आज वह 1200 लीटर प्रति व्यक्ति पर आ चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, 1700 लीटर प्रति व्यक्ति से कम पानी की उपलब्धता गंभीर संकट की ओर इशारा करती है। कमी की यही दर 50 साल के बाद भी जारी रही तो इस गति से हम 200 लीटर प्रति व्यक्ति पर आ जाएंगे और हर तरह के प्रदूषण से सीधे प्रभावित होने लगेंगे। वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 2015 के बीच ऊर्जा के उपयोग में भी आसमानी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों में कहें तो वर्ष 1970 में यह उपयोग अगर 1 यूनिट था तो वर्ष 2010 में 150 और वर्ष 2015 तक 250 यूनिट हो गया। भुखमरी और कुपोषण आज दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक हैं और बढ़ती आबादी के कारण इनके प्रसार में और वृद्धि होगी। यह विडंबना है कि देश-दुनिया की बढ़ती आबादी कभी बड़ी बहस का मुद्दा नहीं बन पाती क्योंकि इससे कई और तरह की बहसें जुड़ी हुई हैं। जनसंख्या के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलू जब भी चर्चा में आते हैं तो कई तरह के विवादों में अटक जाते हैं। जनसंख्या पर चर्चा से हम कतरा नहीं सकते क्योंकि यह विस्फोटक स्थिति में है। दुनिया के हर तीसरे व्यक्ति को भरपेट भोजन हासिल नहीं होता है और आधी आबादी के सिर पर अपनी छत नहीं है। दुनिया में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मात्र 30-40 प्रतिशत लोगों के हिस्से आती हैं। बढ़ती जनसंख्या और सुविधाओं के अभाव ने पलायन के लगातार जारी सिलसिले को जन्म दिया जिससे शहर और गांवों के बीच पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ा है। पिछले 300 वर्षों में औद्योगिक क्रांति व अन्य विकास के चलते हमने तेजी से वनों को खोया है। प्रति वर्ष 1.50 लाख किमी वन के विनाश का प्रतिकूल असर पानी, मिट्टी और हवा पर पड़ेगा ही।

अरबों पेड़ चाहिए

आज की आबादी को देखते हुए हमें पूरी दुनिया में 1000अरब वृक्ष चाहिए जो 830 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड सोख सकें। भारत में एक तरफ नदी, नाले, कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हर सेकंड आबादी में इजाफा हो रहा है। संसाधनों और आबादी में संतुलन होगा, तभी हर व्यक्ति को जीवन के लिए जरूरी आधारभूत वस्तुएं मिल सकेंगी। एक तरफ पानी की कमी का संकट और दूसरी तरफ बाढ़ का प्रकोप- ये दोनों ही जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे हैं। इनसे बचना है तो जनसंख्या नियंत्रित करनी होगी। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से जनसंख्या पर जताई हुई चिंता पूरी तरह जायज है लेकिन सरकार की जनसंख्या नियंत्रण संबंधी योजनाएं तभी सफल हो सकेंगी, जब हम खुद इस दिशा में प्रयत्नशील हों, चैतन्य हों।

रेलवे में पलास्टिक होगा बैन

भारतीय रेलवे ने पर्यावरण को प्लास्टिक के खतरे से बचाने के लिए पहल की है।

रेल मंत्रालय ने रेलवे की सभी यूनिटों को दो अक्टूबर, 2019 से 50 माइक्रॉन से कम मोटाई के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। प्लास्टिक के कचरे के सृजन को न्यूनतम स्तर पर लाने और इसके पर्यावरण अनुकूल निपटारे की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इन निर्देशों पर कड़ाई से पालन 02 अक्टूबर से किया जाएगा, ताकि सभी संबंधित लोगों को 'प्लास्टिक मुक्त भारत' सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। रेल मंत्रालय ने रेलवे की सभी यूनिटों को यह निर्देश भी दिया है कि प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने की शपथ दो अक्टूबर को दिलाई जाएगी। इसके अलावा, रेलवे की सुविधाओं का उपयोग करने वालों को यह निर्देष दिया जायेगा कि किसी भी हाल में वो प्लास्टिक का उपयोग न करें।

ई-रिक्शा रांची में ट्रैफिक के लिये सरदर्द

रांची : ई रिक्शा भले प्रदूषण रहित वाहन हैं। बैट्री से चलने और शोर नहीं करने के कारण यह सुविधाजनक तो हैं, पर जरूरत से ज्यादा तादाद के कारण यह रांची के ट्रैफिक के लिये सरदर्द भी साबित हुये हैं। इनके कारण रांची के महात्मा गांधी मार्ग में हमेंशा जाम की स्थिति बनी रहती है। कम खर्च में कमाई के साधन के तौर पर इसे देख इसकी बेतहाशा खरीददारी हुई और राजधानी की सड़कों पर इनकी उपस्थिति जाम का कारण बनी। अब सरकार ने इन्हें महात्मा गांधी मार्ग में बैन करने का निर्णय लिया है।

फिलीपींस सरकार ने की है अनूठी पहल, छात्रों को कहा है कि, नामांकन या डिग्री तभी मिलेगी जब पेड़ लगाओगे, वन विभाग और शिक्षा विभाग ने मिल कर किया प्रयास

पहल दस पेड़ लगाओ तब होगा नामांकन और मिलेगी स्नातक की डिग्री

- फिलीपींस सरकार ने हाउस बिल 8728 और ग्रजुएशन लीगेसी फोर द एनवाइरनमेंट एक्ट बना रखा है।
- छात्रों को किसी भी प्रकार की भूमि पर पेड़ लगाना अनिवार्य होता है।

फिलीपींस पूर्व का एक देश है जो कभी राजनीतिक उथल पुथल के लिये जाना जाता था। समुद्र में टापुओं वाला यह देश कई तरह की समस्याओं से दो चार रहता है। कभी ड्रग तस्करों, आतंकियों और अपने राष्ट्रपति दुर्तेते के बड़बोलेपन वाला यह देश भी पर्यावरण को लेकर कितना जागरूक है यह उसके कानूनों से हम समझ सकते हैं। फिलीपींस में "ग्रेजुएशन लिगेसी फॉर द एनवायरनमेंट एक्ट" को लागू किया गया है। इसका उद्देश्य सभी स्नातक प्राथमिक, उच्च विद्यालय और कॉलेज के छात्रों को स्नातक के लिए कम से कम 10 पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इस बिल में प्रावधान है कि कि पेड़ों को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में लगाया जाना चाहिएः वन भूमि, मैन्ग्रोव और संरक्षित क्षेत्र, पैतृक जमीन, नागरिक और सैन्य भूमि, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकारी इकाइयों की हरियाली योजना के तहत, निष्क्रिय और परित्यक्त खदान स्थल। और अन्य उपयुक्त भूमि।

वहां तकरीबन 18 लाख छात्र प्रतिवर्ष कॉलेजों में ग्रेजुएशन के लिये आते हैं, और उन सबों को दस पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

स्कूल कॉलेजों को ये कहा गया है कि छात्रों के दस पेड़ लगाने की शर्त को हर हाल में मोनिटर करें।

इस पहल से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 175 मिलियन नए पेड़ लगाए जाएंगे।" एक पीढ़ी के पाठ्यक्रम में 525 बिलियन से कम नहीं लगाया जा सकता है, ''वहां के मंत्री एलेजानो ने बिल के व्याख्यात्मक नोट में बताया कि हम अभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे कि, इनमें सेकितने पेड़ बचेंगे, बल्कि अभी हमारा जोर इस पर है कि युवाओं में वन लगाने की प्रवृति बन जाये। अबर इनमें से दस प्रतिशत पेड़ भी बच गये तो इसका मतलब यह होगा कि इन युवाओं को भविष्य में आनंद लेने

के लिए 525 मिलियन अतिरिक्त पेड़ उपलब्ध होंग और आगे की पीढी पर्यावरणीय नजरियो से भी आश्वस्त रहेगी।पेड़ों को वन भूमि, मैंग्रोव और संरक्षित क्षेत्रों, पैतृक डोमेन, नागरिक और सैन्य आरक्षण, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकारी इकाइयों की हरियाली योजना के तहत, निष्क्रिय और परित्यक्त खदान स्थलों, और अन्य उपयुक्त भूमि में लगाया जाएगा। इन लगाए गए पेड़ों को क्षेत्र के स्थान, जलवायु और स्थलाकृति के लिए उपयुक्त होना चाहिए, और स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों के रोपण के लिए प्राथमिकता होगी। हम उन विदेशी वृक्षों को कभी नहीं लगायेंगे जो यहां की जलवायू को नष्ट करते हों, या भूजल स्तर को नीचे ले जाते हों।

विधेयक के तहत, शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा पर आयोग पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन विभाग (ऊएठफ), कृषि विभाग, कृषि सुधार विभाग, और स्वदेशी पीपुल्स पर राष्ट्रीय आयोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अन्य सरकारी एजेंसियां भी इसमें साथ दे रही है।

ये एजेंसियां नर्सरी स्थापना, अंकुर उत्पादन और साइट की तैयारी, निगरानी और मूल्यांकन और तकनीकी सहायता और विस्तार सेवाओं के लिए जिम्मेदार होंगी। उन्हें सुरक्षा, परिवहन, अग्नि सुरक्षा सुविधाएं और चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जा रही हैं। कुछ प्रारंभिक समस्याओं के बाद अब इस एक्ट के कारण युवाओं में पेड़ लगाने की संस्कृति खुद डेवलप कर गयी है।

जल संरक्षण में लगे जुनूनी लोगों की भी कमी नहीं

बोकारो के मकसूद चार साल में भगीरथ प्रयास कर पहाड़ से गिरते पानी को गांव तक ले आये

सम्मान प्राप्त करते मकसूद

झारखंड में बोकारो थर्मल के कस्बे नूरी नगर के रहनेवाले मकसूद अंसारी ने अकेले प्रयास कर चार सालों में लगभग 20 फीट ऊंचे और 100 फीट लंबा चौड़ा बांध बनाया । जिससे पहाड़ से गिर रहे पानी को अपने गांव तक ला सकें। मकसूद ने जब बांध बनाने की पहल की तो लोगों ने उनका उपहास उड़ाया। वहीं उपहास उड़ाने वाले अब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं।

इस पंद्रह अगस्त को मंत्री अमर बाउरी और बोकारो के तत्कालीन उपायुक्त कृपानंद झा ने मकसूद अंसारी को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है।दरअसल मकसूद अंसारी ने जिद और जुनून से अपने दम पर वो काम किया है, जिसका निर्माण पर सरकारी योजनाओं में लाखों खर्च किए जाते हैं।

पहाड़ से पानी उतर रहा था। तभी मन में आया पहाड़ से गिरते पानी को अपने गांव के करीब ले जाया जाए. इस दौरान आंखों के सामने वो तस्वींरें भी आने लगी कि कैसे गांव में नल से पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहती है। जबकि गर्मियों में पानी के अभाव में कई दिनों तक लोग नहा नहीं पाते हैं। जाहिर है इसके लिए बांध की जरूरत थी. मन में ही ठान लिया है कि यह काम करके रहेंगे। चाहे वक्त और मेहनत जो लगे।

मकसूद की पत्नी जुबैदा बताती हैं कि शुरुआती दिनों में यह नहीं लगा कि इस काम में कई साल लगेंगे। घर वाले की मौके पर उन्हें रोकते-टोकते भी। लेकिन वे मानते कहां थे दिहाड़ी खटने से जब फुर्सत मिलती। कुदाल, गैंता लेकर निकल जाते। कभी

मकसूद बताते हैं कि, मेरे अकेले ही इस काम में भिड़ जाने पर सभी मेरा मजाक उड़ाने लगे, पर मैं विचलित नहीं हुआ। पत्नी ने जरूर इस काम में मेरा साथ दिया। दिन, हफ्ते, महीने और साल बीते पहाड़ से गिरते पानी को थाम लेना आसान नहीं था, पर इसे जिद कहिए या जुनून, हमने उसे थाम लिया।

जाहिर है मकसद साकार हुआ। बेहद सुकून मिला जब आजादी के जश्न के बीच पंद्रह अगस्त को हमें इस काम का सम्मान मिला।इस काम में उन्हें चार साल लगे. लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। वे खुद गैंता-कुदाल चलाते। मिट्टी काटते- ढोते। बांस-बल्ली का जुगाड़ करते। फिलहाल इस बांध में छह फीट पानी है। मकसूद को उनलोगों से कोई शिकायत भी नहीं जो उनके इस जुनून को पागलपन समझ रहे थे। गांव के लोग बताते हैं कि डीवीसी ने सीएसआर फंड के तहत गांव में नल तो लगाया है, लेकिन इतनी आपूर्ति नहीं होती कि हर काम निकल जाए. अब मकसदू के बनाए बांध से बड़ी राहत मिलती दिख रही है। मवेशियों को पीने का पानी मिल रहा है। लोगों के नहाने-धोने में भी काम आता है।

मकसूद अंसारी डीवीसी के निर्माणाधीन ऐश पौंड में दिहाड़ी खटते हैं. इससे उनके घर का गुजारा चलता है। वे बताते हैं,'चार साल पहले अपनी बकरियों को पानी पिलाने नूरी नगर से आगे डीवीसी के निर्माणाधीन ऐश पौंड के बायीं ओर जंगल में गए थे। जंगल में एक छोटा सा नाला बह रहा था जिसमें पहाड़ों से पत्थर उठाकर लाते, कभी बांस- बल्ली काटत. सुबह- सांझ पानी के स्त्रोत के आसपास की मिट्टी को काटने में लगे होते। तमाम ताने से बेपरवाह वे काम करते रहे। पत्थरों से बांधते रहे। उनकी मेहनत देख हमसे भी रहा नहीं जाता। जब लगा कि वे जिद्दी हैं, तो हाथ बंटाने लग गई। मकसूद की बूढ़ी मां मसूरन खातून, को भी खुशी है कि उनके बेटे को इस काम के लिए सरकार ने सराहा है। पर उनके सवाल भी हैं कि क्या मकसूद को रोजगार के लिए कोई सरकारी मदद नहीं मिल सकती। मकसूद ने पर्यावरण संरक्षण का भी काम करते रहे हैं। उन्होंने जब चेकडैम बनाना शुरू किया, तो आसपास के जंगलों में लोगों को पेड़ काटने से रोका। आज चेक डैम के किनारे और आसपास बड़ी संख्या में सखुआ एवं सागवान के पेड़ है। चेक डैम से पानी निकासी का एक छोटा सा नाला भी बनाया गया है, ताकि पानी साफ रहे।मकसूद आते- जाते लोगों से अपील करना नहीं भूलते कि बांध की ओर ओर खुले में शौच कर गंदगी नहीं फैलाएं. चार बेटियों का पिता मकसूद रोजगार के लिए अपने बनाये चेकडैम में मछली और बत्तख पालन करना चाहते है। इसके लिए उन्हें सरकारी मदद की आस है। मुखिया अंजूम आलम कहती हैं कि उन्होंने बेरमो बीडीओ को मकसूद के बनाये गए चेकडैम की जानकारी देकर मदद के लिए कहा है लेकिन फिलहाल कोई मदद की आस अब तक नहीं दिखी है।

पब्लिकबोल से साभार

बेंगलुरू के विश्वनाथ जिन्होंने शहर में एक लाख से अधिक कुओं को रिचार्ज किया है

बेंगलुरु लंबे समय से जल संकट से जूझ रहा है। नीती आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक की राजधानी उन प्रमुख मेट्रो शहरों में से एक होगी जो अगले साल तक मुश्किल जल संकट से दो चार होगा। कई इस मौजूदा समस्या के बारे में अधिक चिंतित हैं और इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं,वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ही विनाशकारी स्थिति को रोककर भविष्य को बचाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।

जल कार्यकर्ता और शहरी योजनाकार विश्वनाथ श्रीकांतैया ऐसे ही शख्स हैं। बेंगलुरू से आकर, उन्होंने न केवल इस आगामी गंभीर पानी की कमी से शहर को बचाने की रणनीति बनाई है, बल्कि सफलता के लिए योजनाओं को निष्पादित करना भी शुरू कर दिया है और कुछ बड़ी सफलतायें भी हासिल की है। विश्वनाथ स्थानीय समुदायों के साथ एक टीम के रूप में कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और अब तक 1 लाख कुओं को रिचार्ज कर चुके हैं और 10,000 कुओं को कार्यात्मक बना चुके हैं।

55 वर्षीय कार्यकर्ता को शहर में खुदाई करने वालों से बड़े पैमाने पर समर्थन भी मिला है। विश्वनाथ ने अपनी टीम के साथ आने वाले दिनों में 1 मिलियन कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उनकी लगन देख कर ये लक्ष्य प्राप्ति भी तय लगता है।

कुओं को कैसे रिचार्ज किया जा रहा है, इस बारे में जानकारी देते हुए, जल कार्यकर्ता कहते हैं, ''ये रिचार्ज कुएं छत के वर्षा के पानी का उपयोग करेंगे और इसे एक्वीफर्स में भेजेंगे, जिससे भूजल की स्थिति में सुधार होगा। यह पारंपरिक तरीका खुदाई करने वाले मजदूरों को बेहतर आजीविका प्राप्त करने में भी मदद करेगा।''

कुओं को रिचार्ज करने और उन्हें नियमित उपयोग के लिए कार्यात्मक बनाने के अलावा, विश्वनाथ ने कर्नाटक भर में उद्योगों और घरों के लिए कई छत पर जल संचयन संरचनाएं भी तैयार की हैं।

पानी की बातचीत के बारे में बात करते हुए, वह कहते हैं, छत के हर वर्ग मीटर के लिए व्यक्ति को रिचार्ज के 20 लीटर स्टोरेज का निर्माण करना पड़ता है, और बिल्डिंग के चारों ओर पक्के क्षेत्र के हर वर्ग मीटर में रिचार्ज के लिए 10 लीटर का स्टोरेज बनाना पड़ता है। रिचार्ज कुँआ न्यूनतम 10 फीट होना चाहिए।

विश्वनाथ ने वरूण नामक एक फिल्टर भी विकसित किया है, जो एक उपकरण है जो वर्षा जल को शुद्ध करता है और इसलिए कोई भी उसकी विधि को आजमा सकता है और दैनिक उपयोग के लिए वर्षा जल का उपयोग कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शहर के कब्बन पार्क में कुछ पुराने

कुओं का भी जीर्णोद्धार कराया है।विश्वनाथ को पानी का महत्व पता है, खासकर इस संकट के दौरान वे कहते हैं, ''हमने करगदाबवी नामक किसी चीज़ के माध्यम से सात कुओं की पहचान की, जो सबसे पुराने कुओं में से एक है, जहाँ करगा उत्सव शुरू होता है। हम तब इसे पारंपरिक अच्छी तरह से खोदने वालों के साथ मिल कर पुनर्जीवित किये। ये कुएं पार्क के लिए एक दिन में 65,000 से 100,000 लीटर पानी दे सकते हैं

इस काम में पैसों की भी जरूरत होती है जो नागरिक भागीदारी के साथ और इंडिया केयर फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है, फ्रेंड्स ऑफ लेक नामक एक समूह का भी साथ मिला है। " विश्वनाथ कहते हैं, "वर्तमान में गंभीर जल संकट के साथ, जल निकायों का कायाकल्प, जल-कुशल फ़सलों को बढ़ाना, और अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रित करना भविष्य में इस तरह के तीव्र जल संकट की पुनरावृत्ति से बचने के सफल तरीके हैं।" इस जल कार्यकर्ता का कहना है, ''हम बहुत से लोगों को विभिन्न जल संरक्षण विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने में अब हम सफल हो रहे हैं। हम एक पारिस्थितिक रूप से चलने वाले वास्तुशिल्प वर्कशॉप को भी चलाते हैं, जहां कई घटकों को डिजाइन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है।'' बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड सहित कुछ कुछ इंजीनियर नीतिगत स्तर पर इन जल संरक्षण रणनीति को कार्यान्वित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। डॉ विश्वनाथ 24 वर्षो से अधिक समय से अपने 2 सक्रिय सदस्यों के साथ इस मुहिम में लगे हुये हैं ।

...पेज 1 का शेष

चने की खेती में झारखंड

कानपुर के माध्यम से पूरे देश के 24 राज्यों के 27 कृषि विश्वविद्यालयों के तहत अखिल भारतीय समन्वित चना अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) का संचालन किया जा रहा है. पूरे देश के विभिन्न केन्द्रों द्वारा अबतक चना की करीब 215 उन्नत किस्में विकसित किये गये हैं। देश में चना का रकबा और उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है. दो दशक पहले देश के 5 लाख हेक्टेयर भूमि में 4 मीट्रिक टन चना का उत्पादन होता था. वर्तमान में देश के 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि में करीब 10.2 मीट्रिक टन चना का उत्पादन होता है।गत वर्ष करीब 13 हजार क्विंटल चना के प्रजनक बीज का उत्पादन हुआ. कुल 342 फसल प्रदर्शन किये गए, जिनमें किसानों के खेतों की अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक उपज मिली.देश में चना फसल क्षेत्र के विस्तार के लिए 90 दिनों की अवधि वाली किस्मों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।आईसीएआर के सहायक महानिदेशक (तेलहन एवं दलहन) डॉ एसके झा ने कहा कि चना फसल का रकबा एवं उत्पादन मामले में देश विश्व का नेतृत्व करता है। देश में चना का आयात में करीब 2.3 मीट्रिक टन की कमी आई है। इक्रीसेट के निदेशक डॉ राजीव कुमार वासनी ने कहा कि देश में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दलहन फसलों की 700 से भी अधिक उन्नत किस्मों को विकसित किया गया है. दलहन की मांग और उत्पादन में स्थायित्व के लिए सतत शोध एवं प्रयासों की जरूरत है।

पूर्वी राज्यों में झारखण्ड प्रदेश मात्र का चना बेहतर प्रदर्शन: डॉ एनपी सिंह, राष्ट्रीय निदेशक

भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईपीआरआई), कानपुर के निदेशक डॉ एनपी सिंह ने बताया की देश में 40 प्रतिशत चना का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है. देश में चना की मांग लगातार बढ़ी है. धान की परती पड़ी भूमि में चना फसल का रकबा बढ़ाना वैज्ञानिकों के लिए गंभीर चुनौती है. वर्तमान में चना उत्पादन बढ़ाने की देश में अनुकूल स्थिति है. भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने चना की कई सूखा सहिष्णु एवं कम अवधि वाली किस्में विकसित किये है.चना फसल के शोध क्षेत्र में इक्रीसेट जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान के जुड़ने से अधिक वैज्ञानिक सोच को बल मिला है. झारखण्ड सहित कई राज्यों में चना फसल के रकबा एवं उत्पादन में बढ़ोतरी देखी जा रही है. झारखण्ड राज्य में चना फसल का रकबा, उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी देखने को मिला.जिसके बेहतर परिणाम आगामी मौसम में देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में 5 सत्रों में चना की नवीन प्रजातियों की खोज एवं पहले से संतुस्त किस्मों की राष्ट्रीय स्तर पर मांग के अनुरूप बीज आपूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में प्रजनक बीज एवं नाभकीय बीज उत्पादन पर चर्चा हुई. बैठक में चना फसल पर उच्च कोटि के प्रदर्शन को अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण के माध्यम से किसानों के खेत में तकनीकी क्षमता दर्शाने की पर विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की सहभागिता से अनुसंधान कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने एवं कार्यक्रमों के आदान - प्रदान करने पर विचार किया गया. बैठक में आगामी फसल मौसम में विभिन्न विषयों पर प्रक्षेत्र कार्यशाला लगाकर अनुसंधान कार्यो की समीक्षा करने पर जोर दिया गया।डॉ सिंह ने कहा कि गत 10 वर्षो में पूर्वी भारत का झारखण्ड ही ऐसा प्रदेश है, जहाँ चना का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता लगातार बढ़ी है. झारखण्ड में दस वर्ष पहले मात्र 30 हजार हेक्टेयर में ही चना की खेती होती थी. आज यह बढ़कर 2.35 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है और उत्पादकता में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है. यह बैठक राज्यों के कृषि विभागों को चना खेती पर परामर्श और आगे कार्य करने की संभावनाओं पर प्रकाश डालेगी. बीएयू राज्य के कृषि विभाग को तकनीकी तथा मांग के अनुरूप प्रजनक बीज प्रदान करेगा, जिसमें आईसीएआर विशेष तौर पर मदद देगी.डॉ सिंह ने कहा कि चना कार्य समुह की इस बैठक में विभिन्न केन्द्रों द्वारा विभिन्न कृषि पारिस्थिकी हेतु चना की 7 उन्नत किस्मों को चिन्हित किया गया.देश में 217 दलहन सीड हब कार्यरत है और पिछले 3 वर्षो में 115 दलहन सीड हब स्थापित किये गये हैं।

झारखंड के औषधीय पौधों के संरक्षण की जरूरतः डॉ शरण

रांचीः बूटी मोड़ स्थित सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परशुरामसभागार में 'औषधीय पौधों के संरक्षण एवंसंवर्द्धन के महत्व' पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन विनोबाभावे विश्वविद्यालय के कुलपति डा. (प्रो.) रमेशशरण ने किया।

इस अवसर पर डा. रमेश शरण ने झारखण्ड के विभिन्न शहरों एवं प्रमुख स्थानों पर मिलनेवाले विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों की विस्तार सेचर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि प्रकृतिके प्रति हमारी बेरुखी और औषधीय पौधों के प्रति हमारी जागरुकता खत्म होने से बहुत सारे औषधीय पौधे विलुप्त हो गये, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी थे। उन्होंने कहा कि देवघर के त्रिकूट पर्वत पर मिलनेवाली कई औषधियां आज देखने को नही मिल रही, और अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, प्रकृति को उनके अपने हाल पर छोड़ दें, तो वे विलुप्त औषधियां पुनः प्राप्त होंगी, क्योंकि प्रकृति में यह सब संभव है, प्रकृति स्वयं उन सारी चीजों का निर्माण करने में सक्षम हैं, जो हमारे लिए बहुपयोगी है।

उन्होंने औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्द्धन विषय पर आयोजित इस एकदिवसीय कार्यशाला की भूरि-भूरि प्रशंसा की, तथा इस प्रकार के आयोजनों से सभी को लाभ उठाने का आह्वान किया, उनका कहना था कि जैसे ही हम औषधी यगुणों वाली पौधों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे, एक तारतम्य बनेगा और फिर इन औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्द्धन का काम आसान हो जायेगा।

डा. रमेश शरण ने कहा कि झारखण्ड में औषधीय गुणों से विभूषित पौधों का अकूत भंडार छिपा है। यहां कई ऐसी जनजातियां हैं, जो उन औषधीय गुणों वालें पौधों के बारे में बहुत विस्तार से जानती हैं। वे आज भी इन औषधीय गुणों से सुसज्जित पौधों, जड़ी-बूटियों को लेकर बाजारों मेंउपस्थित होती हैं, जरुरत हैं, उनके साथ संबंध प्रगाढ़ कर, उन औषधीय गुणों वाले पौधों को जानने और समझने की, जब तक हम उनके साथ प्रेम संबंध को प्रगाढ़ नहीं बनायेंगे, उनसे बेहतर संबंध नहीं बनायेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, हम औषधीय पौधों का संरक्षण व संवर्द्धन करने में कामयाब नहीं हो पायेंगे। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि पूर्व में किसीको खांसी हो जाती थी, तो घर के दादा-दादी उसे तुलसी का काढ़ा पिलाने की कोशिश करते थे, घर-घर में तुलसी का पौधा होता था, लोगों को सलाह दी जाती थी कि सबेरे तुलसी के कम से कम पांच पत्तियां अवश्य खायें, ताकि स्वास्थ्य बेहतर रहे, साथ ही यह भी हिदायत दी जाती थी कि सप्ताह में दो या तीन दिन तुलसी को छूना भी वर्जित है, यानी इसके पीछे साफ उद्देश्य था कि तुलसी का संरक्षण और संवर्द्धन भी हो, नहीं तो केवल उसका दोहन करेंगे तो फिर वह न तो संरक्षित होगा और न ही संवर्द्धित। जब तक इन विचारों को आत्मसात नहीं करेंगे, हमारा आगे बढ़ना संभव नहीं।

कार्यक्रम को बीआइटी मेसरा के फार्मेसी कॉलेजके डा. (प्रो.) के. जयराम कुमार, डा. (प्रो.) एस केझा ने भी संबोधित किया तथा औषधीय पौधों के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की। कॉलेज के निदेशक डा. हरिहर प्रसाद पांडेय ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके प्रांगणमें होने वाले इस विशेष कार्यशाला में इस क्षेत्र के विद्वतजनों ने भाग लिया तथा इसकी सार्थकता को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इसकार्यशाला से सभी लाभान्वित हुए होंगे, तथा समाज को इसका लाभ मिलेगा। इस कार्यशाला के दौरान औषधीय पौधों की एक प्रदर्शनी भीलगाई गई थी, जिसके बारे में कॉलेज के प्राचार्य डा. अमिताभ कुमार ने विशेष जानकारी दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसका लाभ लिया।

ई वाहनों की ऊंची कीमत आड़े आ सकती है साथ ही सारे देश में बिजली की उपलब्धता के साथ चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करना होगा

बैट्री वाले वाहनों को चलाने से पहले करनी होगी तैयारी

- बिना तैयारी के बैट्री वाले वाहनों को चलाने के एलान से ऑटो सेक्टर में आयी मंदी
- ज्यादा कीमत के कारण आम आदमी बैट्री वाले वाहनों को खरीदने में सक्षम नहीं हो पायेगा

एक अप्रैल 2020 से बिकने वाले सभी वाहनों को बीएस-6 उत्सर्जन नियमों का पालन करना होगा। ये वाहन बहुत कम प्रदूषण फैलाएंगे, लेकिन उनकी लागत अधिक आ सकती है। इसकी वजह यह है कि वाहन कंपनियों पर बीएस-4 इंजनों की जगह बीएस-6 इंजन का उत्पादन शुरू करने की लागत आएगी। हालांकि गैर-बीएस 6 वाहनों को भी चलने की मंजूरी होगी। एक अप्रैल की डेडलाइन के आसपास बहुत से विनिर्माता अपने पुराने स्टॉक पर आकर्षक छूट दे सकते हैं। 'गैर-बीएस 6 वाहनों को खरीदने में जोखिम यह है कि जब आप कुछ साल बाद उन्हें बेचना चाहेंगे तो ग्राहक मिलना मुश्किल हो सकता है। सरकार इन वाहनों को चलाने की लागत में भी बढ़ोतरी कर सकती है। वह इनकी जांच के लिए कड़े नियम लागू कर सकती है। गैर बीएस-6 वाहनों के पुराने होने के बाद अच्छी कीमत नहीं मिलने की आशंका है।

आपको कैसे चयन करना चाहिए? पर्यावरण को लेकर जागरूक चालकों, वाहन का भरपूर इस्तेमाल करने वाले लोग और जो महानगरों में रहते हैं और कार को केवल शहर के भीतर ही चलाना चाहते हैं, वे इलेक्ट्रिक वाहन का विकल्प चुन सकते हैं। हाल के बजट में इन वाहनों को खरीदने पर लिए जाने वाले ऋण पर 1.5 लाख रुपये की कर कटौती दी गई है, जो एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है। हालांकि चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का मतलब है कि इन कारों में से ज्यादातर को शहर के बाहर ले जाना बहुत मुश्किल होगा। ग्रामीण इलाकों में बिजली की नियमित आपूर्ति भी एक समस्या है। जो लोग कार खरीदने पर शुरुआत में ज्यादा पूंजी नहीं खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए आईसीईं इंजन चालित कार बेहतर विकल्प है।

भारत में पहले ई-वाहन का इक्का-दुक्का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई के बजट भाषण में ई-वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। तदुपरांत, भारत में इसके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए योजना बनाकर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत ई-वाहन और अन्य पार्ट खरीदने के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली समिति ने चरणबद्ध तरीके से देश में ई-वाहन की बिक्री बढ़ाने और बैटरी के निर्माण के लिए देश में फैक्टरियां स्थापित करने के लिए एक खाका तैयार किया है, जिसके तहत वर्ष 2023 से बड़े पैमाने पर ई-तिपाहिया वाहन और वर्ष 2025 से ई-दो पहिया वाहन (150 सीसी से कम क्षमता वाली) बिकने शुरू हो जाएंगे। आयोग के अनुसार वर्ष 2030 तक देश में 100 प्रतिशत ई-वाहन की बिक्री होने लगेगी। हालांकि, ब्लूमबर्ग के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में कुल वाहन का केवल 6 प्रतिशत ई-वाहन का ही इस्तेमाल किया जाना संभव हो सकेगा। ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के अनुसार ई-वाहन की योजना को भारत में मूर्त रूप देने के लिए कुछ उपायों को अपनाने की जरूरत है, जिसके तहत ई-बसों, ई-टैक्सियों और ई-दोपहिया वाहनों को सड़कों पर उतारने, निजी वाहनों के उपयोग पर लगाम लगाने, गैर-मोटर चालित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने आदि की जरूरत है, ताकि कार्बन उत्सर्जन, पेट्रोलियम आयात, सड़कों पर भीड़ आदि में कमी आ सके। टेरी नई दिल्ली में स्थिति एक शोध संस्थान है, जो ऊर्जा, पर्यावरण और संवहनीय विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। टीईआरआईके मुताबिक ई-वाहन को अपनाने के लिए 4 आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पहले उपाय के तहत सभी हितधारकों, जैसे; उपयोगकर्ताओं, ई-वाहन निर्माताओं, बिजली और तेल विपणन कंपनियों आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे ई-वाहन से जुड़ी समस्याओं को समझने एवं उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। दूसरे उपाय के तहत इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना, बैटरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक कारोबारी मॉडल शुरू करना जैसे बुनियादी ढांचे विकसित करने की जरूरत है। तीसरे उपाय के तहत देश के 102 शहरों में जहां वायु की गुणवत्ता पर्यावरण मानकों के अनुकूल नहीं है; में गैर-मोटर चालित वाहन जैसे, साइकिल का ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग करने की जरूरत है। टेरी के विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय शहरों में यात्रा की 60 फीसद लंबाई 5 किमी से कम है, और 80 फीसद 10 किमी से कम है। यदि 5 किलोमीटर की औसत दूरी को साइकिल से और 10 किलोमीटर की औसत दूरी के 50 प्रतिशत हिस्से को भी साइकिल से तय किया जाए तो पर्यावरण को तो लाभ होगा ही साथ ही लगभग 1,435 अरब रुपये की बचत भी होगी। चौथे उपाय के तहत बैटरी निर्माण की प्रौद्योगिकी के विकास के लिए देश में दीर्घकालिक नीति को बनाने के साथ-साथ व्यवस्थित अनुसंधान की नीति को भी बढ़ावा देने की जरूरत है।

टेरी का यह भी मानना है कि वर्ष 2030 तक केवल ई-वाहनों की बिक्री की अनुमति के लिए नीति आयोग का हालिया प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। उनका यह अनुमान अतिशयोक्तिपूर्ण भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर ई-वाहन को सड़क पर उतारने वाली योजना को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने जल्दीबाजी में बीएस-4 गाडियों को तय समय-सीमा के अंदर बंद करने की घोषणा कर दी, जिसके कारण बीएस-4 गाड़ियों की बिक्री में कमी आना शुरू हुआ और थोड़े ही समय में वाहन क्षेत्र मंदी के चपेट में आ गया। आज हालात इतने संजीदा हैं कि समग्र अग्रणी संकेतक (सीएलआई) जो 33 प्रमुख संकेतकों का समूह वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में वृद्धि के मामले में नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शा रहा है। इस तरह, चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के ताजा अनुमान 6.9 प्रतिशत के विकास लक्ष्य को भी हासिल करना आसान नहीं होगा। वहीं बिजली के अलावा भी ई-वाहन के सपने को साकार करने की राह में अनेक बधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा देशभर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है। समस्या ई-वाहन की ज्यादा कीमत भी है। जब तक ई-वाहन सस्ती नहीं होगी,आमजन के लिए इसे खरीदना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि ई-वाहन के सपने को साकार करने के लिए जल्दबाजी करने से समस्या कम होने के बजाय बढ़ सकती है।

फोटो न्यूज

गिरिडीह जिले के फुलजोरी के संतोष महली ने बांस से ही भारत माता की मूर्ति बना दी। संतोष महली के कला काबिले तारीफ है।

प्लास्टिक का कहर : ये कोई सड़क या कचड़ा डंप की हुई जगह नहीं है। लातेहार से हमारे एक पाठक ने ये तस्वीर भेजी है, जो किसी खेत की है। खेत में आस पास के लोगों ने इतना प्लास्टिक फेंक दिया कि, जब किसान ने इसे जोत कर खेती करना चाहा तो सिर्फ प्लास्टिक निकला।

कहने को इतनी सख्ती और पहरेदारी के दावे के बावजूद गौतस्करी काबू में क्यों नही?

झारखंड से होकर नहीं रूक रही गौतस्करी

●कभी सोसाइटी फार द प्रिवेंसन ऑफ क्रुएलिटी आफ द एनिमल्स के सदस्यों पर खुद ही गो तस्करी में लिप्त रहने की बात सामने बायी। कुछ सुत्रों और स्टिंग किये गये वीडियो को अगर सच माने तो इसके सदस्य पुलिसिया वर्दी पहन कर पशु क्रूरता से बचाने के नाम पर गोवंशियों के तस्करी में खुद शामिल रहे थे और तस्करों को उल्टे पुलिस से बचाने का काम करते थे। लंबे समय तक इनके कृत्य का पता ही नहीं चला।

●आज ये स्वीकार करना मुश्किल है कि, बिहार या यूपी से गोवंशियों को लाद कर चला ट्रक इतने सारे थानों, पुलिस को चकमा देकर झारखंड होकर बंगाल चला जाता होगा? और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगती होगी?

रांची: गुरूवार की रात रांची के हटिया में कई ट्रकों को स्थानीय लोगों ने रोक लिया। सभी ट्रकों में गोवंश को ठूंस कर उन्हें तस्कर बंगाल ले जा रहे थे। ट्रक ड्राइवरों और स्थानीय लोगों में टकराव शुरू हो गया। तस्करों की संख्या स्थानीय लोगों से ज्यादा थी, वो ग्रामीणों पर भारी पड़ने लगे, जगरनाथपुर थाने को फोन लगाया गया, लेकिन थानेदार अनूप कर्मकार ने फोन रिसीव नहीं किया तस्कर दो सौ में से तकरीबन 130 गोवंशियों को लेकर बंगाल की ओर भाग निकले। सत्तर के करीब गोवंशियों को स्थानीय लोगों ने अपने प्रयास से छुड़ा लिया। अगले दिन पुलिस लाव लश्कर के साथ वहां पहुंची। थानेदार अनूप कर्मकार से जब समय पर स्थानीय लोगों की मदद को न पहुंचने का कारण पूछा गया तो उनका कहना था कि, अननोन फोन नंबर हम नहीं उठाते। थानेदार अगर रात्रि में अनजान फोन नंबर रिसीव ही नहीं करे, तो यह दलील गले नहीं उतरती क्योंकि अपराध का कोई वक्त नहीं होता, और पुलिस को कभी भी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। हालांकि अगले दिन सुबह पुलिस दल बल के साथ पहुंची और मुआयना भी किया।

पूरे वाकये में कई पेंच हैं और समझा जा सकता है कि, गौतस्करी आखिर क्यों नहीं रूकती? भले गोवंशी एक बड़ी आबादी के लिये आस्था की चीज होंगे, पर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जो इससे होने वाली कमाई के लिये इस-की तस्करी में लिप्त है। क्या जगरनाथपुर थाने से इन ट्रकों के भाग जाने के बाद आगे के थानों में खबर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि यहां से बंगाल की सीमा बहुत दूर है और उन्हें झारखंड में ही रोका जा सकता था। क्या ये संभव है कि सौ दो सौ मवेशी लदे कई ट्रक बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश से बंगाल की ओर चलें और वो दो तीन राज्यों की पुलिस थाने से बचते हुये बंगाल में प्रवेश कर जायें। बेशक इस तस्करी में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। इन्हें सकुशल बंगाल पहुंचाने में आखिर कौन काम करता है?

●अब ये बातें पुरानी हो गयी हैं कि इन मवेशियों की आखों में हरी मिर्च और अदरख का रस डाल दिया जाता है जिससे उनकी आंखों में जलन होती रहे और ट्रकों में वह शांत रहते हैं।● पिछले साल जमशेदपुर में बड़ी लग्जरी कारों में पीछे की सीट निकाल कर उसमें बांधकर एक गाय को बिठा कर उसकी तस्करी हो रही थी। लग्जरी कार में गाय के रहने से किसी को शक भी नहीं होता था।●बंगाल में गोवंश लदे ट्रकों के प्रवेश के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह अब वह किसी दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर गया। जहां देश का कानून बेमानी हो जाता है।●गौतस्करों के लिये बिहार, झा-रखंड के पुलिस और कथित गौरक्षकों व एसपीसीए से डील कर दूसरी बाधा बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की पहरेदारी होती रही। बंगाल में इन गौतस्करों के पास दर्जनों हथकंडे होते हैं बांग्लादेशी सीमा में गोवंशियों को पहुंचाने के। ●इन गौतस्करों ने तो बांस और रस्सी से ऐसे ऐसे क्रेननुमा उपकरण बना रखे हैं कि, कुछ मिनटों तक बीएसएफ की पहरेदारी से मौका मिला नहीं कि वो इन क्रेनों में गाय बैलों को बांध कर बांग्लादेश सीमा पर लगे ऊंचे बाड़ों से उस पार भेज देते हैं।● हाल में इन तस्करों ने नया तरीका इजाद कर लिया है जिसमें केले के दो पेडों के बीच एक मवेशी को बांध कर नदी भारत की ओर से छोड़ देते हैं, मवेशी तैरते हुये बांग-लादेश की सीमा में चले जाते हैं जहां उन्हें पकड़ लिया जाता है। ●केले के पेड़ों की वजह से मवेशी लंबी दूरी तक तैर पाते हैं वो डूबते नहीं। जब बीएसएफ वालों ने उनकी इस तरकीब को पकड़ लिया तो तस्करों ने बीएसएफ को नुकसान पहुंचाने के मकसद से केले के इन पेड़ों में विस्फोटक भी बांधने शुरू कर दिये।● ऐसे दर्जनों वाकये हैं जिसमें तस्करों ने पुलिस की कम तादाद देख चेकिंग के दरम्यान उन पर ट्रक चढा दिया या पीछा करने वाले पुलिसकर्मी की ही हत्या कर दी। स्पष्ट है गोवंश की तस्करी झारखंड होकर फल फूल रही है।

रामकृष्ण विद्यानिकेतन

(स्वामी विवेकानन्द मिशन द्वारा संचालित)

गड्डगाँव, बेडो रोड राँची – 835202 (झारखण्ड)

स्वामी विवेकानन्द मिशन के शैक्षणिक इकाई रामकृष्ण विद्यानिकेतन गड्डगाँव, बेडो राँची में भारतीय संस्कृति सभ्यता के धरोहर को स्थापित करने हेतु मिशन द्वारा २०१४ में विद्यालय का स्थापना किया गया. मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान शैक्षणिक एवं प्रतियोगी माहौल को देखते हुए संस्कारयुक्त शिक्षा का सूत्रपात कर प्रारंभिक स्तर से ही लघु-उद्योग, रोजगारोन्मुखी तकनीकी (व्यवसायिक) प्रशिक्षण, खेल-कूद, संगीत-नृत्य, कम्प्युटर एवं कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण मार्गदर्शन कर रोजगार-स्वरोजगार में अंशिक ही सही लेकिन एक उदाहरण समाज में स्थापित करने हेतु मिशन परिवार संकल्पित है.

contact : 07061209090, email rkvidyaniketan14@gmail.com

किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है ये खंभा

मौत को निमंत्रण देता बिजली का खम्बा : तस्वीर रांची जिला के बुण्डू प्रखण्ड अंतर्गत एडकेया गांव की है। लगभग सात साल पहले यहां बिजली पहुंची। आज हालत ये है कि खम्बा लगभग 60 डिग्री झुक गया है। कभी भी जानलेवा दुर्घटना घट सकती है। *फोटो : सिदाम*

अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोपा डोभा का दौर जारी है 15 अगस्त तक रोपा हो जाता था लेकिन इस साल खुंटी में अबतक किया जा रहा रोपाई का काम। हालांकि ताड़ में मड़ुआ, मक्का समेत अन्य खेती अभी लहलहा रही है ।

सबसे लंबी गर्दन और शरीर पर चितकबड़े डिजाइन वाला और बच्चों के मन में कई किरदारों वाला यह अफ्रिकी जीव है खतरे में

तो क्या लुप्त हो जायेंगे जिराफ?

संयुक्त राष्ट्र की लुप्तप्राय जीवों के कारोबार को नियमबद्ध करने वाले विश्व वन्यजीव संरक्षण के कंवेशन में जिराफ के अंगों के वैध कारोबार को अंतरराष्ट्रीय नियमों में बांधने की कोशिश की गई है.

पहली बार जिराफों को खतरे में पड़े जीवों की सूची में डालने की बात हो रही है. इसका पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वालों और खासकर उप-सहारा अफ्रीकी देशों ने स्वागत किया है. विश्व वन्यजीव संरक्षण सम्मेलन में हुई वोटिंग में सम्मेलन का आयोजन करने वाली समिति यानी साइट्स ने कुछ प्रस्तावों की रूपरेखा सामने रखी. इन उपायों से जिराफ के शरीर के हिस्सों के व्यापार को नियंत्रित करने का काम होगा. जिराफ की खाल, हड्डियों की नक्काशी और मांस के व्यापार पर खास नजर होगी हालांकि इस पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जाएगा. इन उपायों को 21 के मुकाबले 106 वोटों से पास कर दिया गया. सात देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया.

वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसायटी के इंटरनेशनल पॉलिसी की वाइस प्रेसिडेंट सुजन लीबरमान का कहना है, "इतने सारे लोग जिराफ के बारे में जानते हैं कि उन्हें लगता है बहुत सारे जिराफ होंगे. जैसे दक्षिण अफ्रीका में भले ही लगता हो कि वे ठीक होंगे लेकिन असल में गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं." लीबरमान बताती हैं कि पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी अफ्रीका के हिस्सों में जिराफ खास तौर पर खतरे में हैं .सोसायटी का मानना है कि जिराफ जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं, उसके कारण उनकी जनसंख्या घट रही है. जिराफ के रहने की जगह कम होती जा रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण ज्यादा सूखा पड़ने लगा है और उनके अंगों के अवैध व्यापार के लिए जिराफ की जान का खतरा बढ़ता जा रहा है. सदस्य देशों को जिराफ के अंगों के निर्यात का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा जो फिलहाल केवल अमेरिका कर रहा है। इसके साथ ही कारोबार के लिए परमिट लेना भी अनिवार्य किया जाएगा।अफ्रीकन वाइल्डलाइफ फाउंडेशन की मैना फिलिप मुरुथि का कहना है, "पिछले 30 सालों में ही जिराफों का आबादी में 40 फीसदी से अधिक कमी आई है. अगर ऐसा चलता रहे तो हम उन्हें खो देंगे." केन्या में भी जिराफ की आबादी तेजी से कम हो रही है. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 1985 से 2015 के बीच अफ्रीका में जिराफों की संख्या 40 फीसदी घट कर एक लाख तक आ गई. फिर भी अफ्रीका के सभी देश इसे लेकर सहमत नहीं हैं. तंजानियाके प्राकृतिक संसाधन और पर्यटन मंत्रालय में वन्यजीव निदेशक मौरुस मसूहा ने कहा, "मुझे इस निर्णय का समर्थन करने की कोई वजह नहीं दिखती. क्योंकि तंजानिया में तो जिराफों की आबादी बढ़ ही रही है." उन्होंने बताया कि तंजानिया के आधे से ज्यादा जिर-ाफ सेरेंगेटी इकोसिस्टम के सुरक्षित माहौल में रहते हैं .साइट्स के अधिकारी टॉम डे मॉयलेनार ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य जिराफ के अंगों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ध्यान दिलाना था. जिराफ के अंगों का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है. अमेरिका के भीतर भी जीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि ट्रंप प्रशासन जिराफ को अमेरिका के इन्डेजर्ड स्पिशीज एक्ट के अंतर्गत लेकर आए. एक हफ्ते पहले ही ट्रंप प्रशासन ने इस एक्ट को और हल्का बनाए जाने की बात कही है .सहारा के आसपास के अफ्रीकी इलाकों में अब केवल 97,500 जिराफ बचे हैं. इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) के मुताबिक 1985 की तुलना में यह संख्या करीब 40 फीसदी कम है. वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यूरोप में पाया जाने वाला बोहिलिनिया नाम का जीव चीन और भारत की तरफ चला आया. बोहिलिनिया को आधुनिक जिराफ का पूर्वज माना जाता है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty
info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511 Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

सन कम्युनिकेशन द्वारा अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2 टीवीएस गली रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित एवं मैसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित। प्रकाशक सह कार्यकारी संपादक : मनोरंजन सिंह, संपादकः मनोज कुमार शर्मा*, आर.एन.आइ. नंबर : JHAHIN00962. email:greenrevolt2019@gmail.com. Ph. 8539978825, 8825374626. इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन ही होंगे।